IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कोठारी आयोग से NEP 2020 तक: निरंतरता और परिवर्तन

परमजीत

शोधार्थी, इतिहास विभाग, देश भगत यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब

डॉ. हवलदार भारती

असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, देश भगत यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब

सार

प्रस्तुत शोध-पत्र 1964-66 *के कोठारी आयोग से लेकर* 2020 *की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक की यात्रा में भारतीय शिक्षा नीति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्त्वों का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन इस केंद्रीय प्रश्न को संबोधित करता है कि भारत की शिक्षा नीति के पाँच दशकों में कौन-से मूल्य और उद्देश्य अपरिवर्तित रहे, और कहाँ-कहाँ आमूल परिवर्तन हुए। सरकारी दस्तावेज़ों, आयोग-रिपोर्टों और शैक्षणिक साहित्य के दस्तावेज़-विश्लेषण पर आधारित यह शोध दिखाता है कि* NEP 2020 *कोठारी आयोग की वैचारिक धरोहर को आगे बढ़ाता है, किंतु वैश्वीकरण और डिजिटल युग की माँगों के अनुरूप उसे पुनर्परिभाषित भी करता है।*

मुख्य शब्द: कोठारी आयोग, NEP 2020, शिक्षा नीति, निरंतरता, परिवर्तन, राष्ट्र-निर्माण, भारत

1. प्रस्तावना

1964 में जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम. सी. छागला ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की, तब भारत एक चौराहे पर खड़ा था। चीन से युद्ध में पराजय (1962) ने आत्मविश्वास को हिला दिया था, नेहरू का निधन हो चुका था, और आर्थिक विकास की गति धीमी थी। इन्हीं संकट के क्षणों में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की जो भारतीय शिक्षा के लिए आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। उसके ठीक 54 वर्ष बाद, 2020 में डॉ. कस्तूरीरंगन समिति ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की एक ऐसे भारत के लिए जो विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहाँ स्मार्टफ़ोन क्रांति हो चुकी है, जहाँ IIT और IIM विश्व-प्रसिद्ध हैं, किंतु जहाँ आज भी करोड़ों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं।

यह शोध-पत्र इन दोनों ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे: (1) कोठारी आयोग के किन विचारों को NEP 2020 ने आत्मसात किया? (2) किन क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन आए? (3) जो अधूरे सपने कोठारी ने देखे थे, उन्हें NEP 2020 ने कैसे संबोधित किया?

इस अध्ययन का तर्क है कि कोठारी आयोग और NEP 2020 के बीच एक जीवंत वैचारिक धागा है दोनों शिक्षा को समाज-परिवर्तन का साधन मानते हैं किंतु उनके बीच राजनीतिक संदर्भ, आर्थिक प्राथमिकताएँ और वैश्विक शिक्षा-दर्शन में जो बदलाव आए हैं, उनसे नीति का स्वरूप भिन्न हो गया है।

2. शोध-पद्धति और स्रोत

यह एक तुलनात्मक दस्तावेज़-विश्लेषण है। मुख्यतः दो प्राथमिक दस्तावेज़ों कोठारी आयोग की रिपोर्ट "एजुकेशन एवं नेशनल डेवलपमेंट" (1966) तथा "नेशनल शिक्षा नीति 2020" के मध्य तुलना की गई है। इसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, RTE अधिनियम 2009 और कस्तूरीरंगन समिति का मसौदा (2019) भी सहायक स्रोत के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। द्वितीयक स्रोतों में कुमार (2005), तिलक (2004, 2018), बेतेइल्ले (2010), नाम्बिस्सन (2010), रैना (2002), चट्टोपाध्याय (2021), भट्टाचार्य (2021), देशपांडे (2020), तथा ASER रिपोर्टें (2005-2019) सम्मिलित हैं। तुलना के लिए पाँच आयाम निर्धारित किए गए हैं: (1) शैक्षणिक संरचना, (2) भाषा-नीति, (3) सामाजिक न्याय, (4) उच्च शिक्षा, और (5) शिक्षक एवं मूल्यांकन।

3. कोठारी आयोग: एक वैचारिक समीक्षा

3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

"भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है।". यह एकल वाक्य कोठारी आयोग (1966, p. 1) का सार है। 17 सदस्यों वाले इस आयोग में भारतीय और विदेशी (मुख्यतः अमेरिकी) शिक्षाविद् थे। आयोग ने दो वर्षों में देश के कोने-कोने का दौरा किया और एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की परिकल्पना की जो वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। रैना (2002) के अनुसार, कोठारी आयोग अद्वितीय इसलिए था क्योंकि उसने शिक्षा को केवल सरकारी सेवा नहीं, बल्कि "राष्ट्रीय निवेश" की दृष्टि से देखा। उसकी भाषा व्यावहारिक थी, उसके आंकड़े ठोस थे और उसकी सिफारिशें तत्काल लागू करने योग्य थीं।

3.2 कोठारी आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ

कोठारी आयोग की केंद्रीय सिफारिशें इस प्रकार थीं: (1) 10+2+3 की राष्ट्रव्यापी शैक्षिक संरचना; (2) सामान्य विद्यालय प्रणाली जहाँ समाज के सभी वर्ग एक साथ पढ़ें; (3) GDP का 6% शिक्षा पर व्यय; (4) त्रिभाषा सूत्र; (5) विज्ञान एवं गणित शिक्षा को प्राथमिकता; (6) व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार; (7) शिक्षक-प्रशिक्षण और उनकी सेवा-शर्तों में सुधार; (8) अनुसूचित जाति-जनजाति की शिक्षा पर विशेष ध्यान (कोठारी आयोग, 1966)। इन सिफारिशों का आधार एक नेहरूवादी-समाजवादी दृष्टि थी जिसमें राज्य ही शिक्षा का मुख्य प्रदाता और संरक्षक था। कुमार (2005) का मत है कि कोठारी आयोग ने "सार्वजनिक कल्याण" के रूप में शिक्षा की अवधारणा को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुँचाया।

4. NEP 2020: एक नई दृष्टि

4.1 ऐतिहासिक संदर्भ

NEP 2020 की पृष्ठभूमि में कई परिवर्तन थे: भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा था, 2022 तक "नया भारत" की संकल्पना थी, और वैश्विक स्तर पर चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0), आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की चुनौतियाँ सामने थीं। साथ ही ASER रिपोर्टें (2005-2019) यह भी बता रही थीं कि RTE के बावजूद "सीखने की गुणवत्ता" में गिरावट आई है। भट्टाचार्य (2021) ने रेखांकित किया है कि NEP 2020 का निर्माण एक ऐसे राजनीतिक परिवेश में हुआ जो 1964-66 से सर्वथा भिन्न था अब राज्य की भूमिका सीमित करने, बाज़ार को स्थान देने और "भारतीयता" की पुनर्खोज पर बल था।

4.2 NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

NEP 2020 (p. 4-6) की नई संरचना 5+3+3+4 है जो 10+2 के पुराने ढाँचे को तोड़ती है। इसमें पाँच वर्ष की आयु से (आंगनबाड़ी/बालवाटिका) शिक्षा प्रारंभ होती है। प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं: (1) मातृभाषा में कक्षा-5 (अधिमानतः कक्षा-8) तक शिक्षण; (2) कला-विज्ञान-वाणिज्य का कठोर विभाजन समाप्त; (3) बहु-प्रवेश/बहु-निकास उच्च शिक्षा; (4) "अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स"; (5) भारतीय ज्ञान परंपराओं का पाठ्यक्रम में समावेश; (6) 2035 तक उच्च शिक्षा में GER 50% का लक्ष्य; (7) ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षा का विस्तार।

5. निरंतरता के आयाम

5.1 शिक्षा को राष्ट्र-निर्माण का माध्यम मानना

कोठारी आयोग ने कहा था: "शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है।" (कोठारी आयोग, 1966, p. 5)। NEP 2020 भी इसी भावना को दोहराती है "यह नीति एक भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जो हमारे राष्ट्र को सतत रूप से एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान समाज में रूपांतरित करने में प्रत्यक्ष योगदान दे।" (NEP 2020, p. 4)। दोनों दस्तावेज़ों में शिक्षा को केवल रोज़गार-प्रशिक्षण नहीं, बल्कि नागरिक-चरित्र निर्माण का माध्यम माना गया है। तिलक (2018) के अनुसार, यह निरंतरता भारतीय शिक्षा-दर्शन की एक सुदृढ़ परंपरा को दर्शाती है जो उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवाद से उत्पन्न हुई थी।

5.2 त्रिभाषा सूत्र और मातृभाषा को महत्त्व

कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र (क्षेत्रीय भाषा + हिंदी + अंग्रेज़ी) की सिफारिश की थी और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। NEP 2020 ने इस सिफारिश को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे और मज़बूत किया: "कम-से-कम कक्षा 5 तक, और यथासंभव कक्षा 8 तथा उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगा।" (NEP 2020, p. 13)। देशपांडे (2020) का विश्लेषण है कि मातृभाषा में शिक्षा के प्रश्न पर कोठारी और कस्तूरीरंगन दोनों सहमत हैं यह भाषाई न्याय और संज्ञानात्मक विकास

दोनों दृष्टियों से आवश्यक है। किंतु व्यवहार में दोनों नीतियाँ अंग्रेज़ी माध्यम की निजी शिक्षा की बढ़ती माँग के विरुद्ध संघर्ष करती रही हैं।

5.3 विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल

कोठारी आयोग ने विज्ञान एवं गणित शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया था। इसी के परिणामस्वरूप NCERT की स्थापना हुई और विज्ञान शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित किए गए। NEP 2020 इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कोडिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और डेटा साइंस को पाठ्यक्रम में जोड़ती है। दोनों नीतियाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मौलिक शैक्षणिक मूल्य मानती हैं जो संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में भी वर्णित है।

5.4 सामाजिक समता का संकल्प

कोठारी आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश की थी। NEP 2020 में भी "सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी)" के लिए विशेष अध्याय (अध्याय 6) है जिसमें कहा गया है "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना इस नीति का मुख्य केंद्रबिंदु है।" (NEP 2020, p. 26)। नाम्बिस्सन (2020) के अनुसार, दोनों नीतियों में सामाजिक समावेश की भाषा मज़बूत है किंतु क्रियान्वयन के तंत्र भिन्न हैं।

5.5 शिक्षक की केंद्रीय भूमिका

कोठारी आयोग ने घोषित किया था: "शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न कारकों में... शिक्षकों की गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण हैं।" (कोठारी आयोग, 1966, p. 102)। NEP 2020 भी इसी भावना को दोहराती है: "शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं और इस प्रकार हमारे देश के भविष्य को भी।" (NEP 2020, p. 5)। दोनों दस्तावेज़ शिक्षक-प्रशिक्षण की उपेक्षा को भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी कमज़ोरी मानते हैं।

6. परिवर्तन के आयाम

6.1 शैक्षणिक संरचना: 10+2 से 5+3+3+4

कोठारी आयोग की सबसे प्रभावशाली सिफारिश 10+2+3 की संरचना थी जो 1968 की नीति में स्वीकृत हुई और देशभर में लागू की गई। यह ढाँचा पाँच दशकों तक चला। NEP 2020 ने इसे पूरी तरह बदलकर 5+3+3+4 की नई संरचना अपनाई जो "मूलभूत चरण" (3-8 वर्ष), "तैयारी चरण" (8-11 वर्ष), "माध्यमिक चरण" (11-14 वर्ष) और "द्वितीय चरण" (14-18 वर्ष) में विभाजित है (NEP 2020, p. 7)। यह परिवर्तन केवल संरचनात्मक नहीं, बल्कि दार्शनिक भी है। NEP 2020 वाइगोत्स्की और पियाजे की विकासात्मक मनोविज्ञान की अवधारणाओं पर आधारित है आयु-आधारित सीखने के चरणों को मान्यता देना इसकी नवीनता है। चट्टोपाध्याय (2021) का मत है

कि यह संरचना पश्चिमी शैक्षणिक मॉडलों से प्रेरित है जबकि कोठारी की संरचना भारत की परिस्थितियों के अनुरूप थी।

6.2 सामान्य विद्यालय प्रणाली बनाम बहुलवादी प्रणाली

कोठारी आयोग की सबसे महत्त्वाकांक्षी और सबसे उपेक्षित सिफारिश थी "कॉमन स्कूल सिस्टम" (CSS) एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रधानमंत्री का बच्चा और रिक्शाचालक का बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ें। कोठारी ने CSS को सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का आधार माना था: "कॉमन स्कूल सिस्टम का कार्यान्वयन… देश में आवश्यक सबसे तात्कालिक शैक्षिक सुधार है।" (कोठारी आयोग, 1966, p. 103)। NEP 2020 में CSS का उल्लेख तक नहीं है। इसके बजाय निजी विद्यालयों और संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ाने पर बल है। बेतेइल (2010) और तिलक (2018) दोनों ने CSS की अनुपस्थिति को NEP 2020 की सबसे बड़ी खामी बताया है। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं, आमूल है इसका अर्थ है कि राज्य एक समान शिक्षा-प्रणाली की ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहा है।

6.3 शिक्षा में राज्य की भूमिका: प्रदाता से नियामक

कोठारी आयोग की परिकल्पना में राज्य शिक्षा का मुख्य प्रदाता था। GDP का 6% व्यय का लक्ष्य और सार्वजनिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर बल इसी दर्शन की अभिव्यक्ति थे। NEP 2020 में राज्य की भूमिका "प्रदाता" से बदलकर "नियामक और सुविधादाता" हो गई है। PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को प्रोत्साहन और निजी परोपकारी संस्थाओं (फिलैंथ्रॉपिक ऑर्गनाइजेशन्स) को शिक्षा-क्षेत्र में आमंत्रण इस परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। तिलक (2018) की आलोचना है कि जब तक सरकार GDP का 6% शिक्षा पर खर्च नहीं करती जो कोठारी का 1966 का स्वप्न था तब तक NEP 2020 की भव्य घोषणाएँ कागज़ पर ही रहेंगी। इस मुद्दे पर दोनों नीतियाँ एक ही लक्ष्य घोषित करती हैं किंतु व्यवहार में इस लक्ष्य से दूरी बनी रहती है।

6.4 उच्च शिक्षा: एकाधिकार से बहुलवाद

कोठारी आयोग की उच्च शिक्षा दृष्टि विश्वविद्यालय-केंद्रित थी जहाँ UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) एकमात्र नियामक संस्था थी। NEP 2020 ने इस ढाँचे को पूरी तरह बदल दिया है। UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग-अलग नियामकों को समाप्त कर एकीकृत "भारतीय उच्च शिक्षा आयोग" (HECI) बनाने की परिकल्पना है। इसके साथ ही "मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़" (MERUs) की अवधारणा, नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की परंपरा से प्रेरणा, और "अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स" जैसे नवाचार NEP 2020 को कोठारी से मूलतः भिन्न बनाते हैं। भट्टाचार्य (2021) इसे "उदारवादी शिक्षा की ओर वापसी" कहते हैं।

6.5 भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

कोठारी आयोग का दृष्टिकोण मुख्यतः नेहरूवादी-वैज्ञानिक था जिसमें आधुनिकता और पश्चिमी ज्ञान-परंपरा को केंद्र में रखा गया था। आयोग ने "वैज्ञानिक दृष्टिकोण" और "तर्कवाद" को शिक्षा का आधार माना। NEP 2020 में

एक स्पष्ट वैचारिक बदलाव दिखता है भारतीय ज्ञान प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने का आग्रह। संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना, योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन को उच्च शिक्षा में स्थान देना ये NEP 2020 की विशिष्टताएँ हैं (NEP 2020, p. 46)। चट्टोपाध्याय (2021) और देशपांडे (2020) दोनों इस पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि IKS का अनालोचनात्मक समावेश "शिक्षा का भगवाकरण" का जोखिम उठाता है।

6.6 प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा

कोठारी आयोग के समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन शिक्षा की कल्पना भी नहीं थी। NEP 2020 इस संदर्भ में एक पूर्णतः नई नीति है। इसमें "नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम" (NETF) की स्थापना, e-content, virtual labs, DIKSHA प्लेटफ़ॉर्म और AI का उपयोग जैसे प्रावधान हैं। COVID-19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता और सीमाएँ दोनों उजागर कर दिए। ASER (2021) के अनुसार, महामारी के दौरान लगभग 40% ग्रामीण छात्रों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। यह "डिजिटल विभाजन" NEP 2020 की तकनीक-आधारित रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती है।

7. कोठारी के अधूरे सपने और NEP 2020

कोठारी आयोग के कुछ स्वप्न ऐसे हैं जो न 1968 की नीति में पूरे हुए, न 1986 में, और अब NEP 2020 उन्हें नए रूप में संबोधित करती है। सबसे पहला: GDP का 6% शिक्षा पर व्यय। भारत आज भी शिक्षा पर GDP का लगभग 3.5-4% ही खर्च करता है (विश्व बैंक, 2020)। NEP 2020 इस लक्ष्य को दोहराती है किंतु वित्तीय प्रतिबद्धता का कोई बाध्यकारी तंत्र नहीं है। तिलक (2018) इसे "बार-बार किया गया वादा, बार-बार हुई विफलता " कहते हैं। दूसरा: शिक्षक की दशा सुधारना। कोठारी ने कहा था कि जब तक शिक्षकों को सामाजिक सम्मान और उचित वेतन नहीं मिलेगा, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। NEP 2020 इस बात को स्वीकार करती है और 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed. कार्यक्रम प्रस्तावित करती है। किंतु "संविदा शिक्षक" और "पैरा-शिक्षक" की व्यापक नियुक्तियाँ इस भावना के विरुद्ध हैं। तीसरा: व्यावसायिक शिक्षा। कोठारी ने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने पर बल दिया था। NEP 2020 इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाती है कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप का प्रावधान। यह कोठारी की भावना के अनुरूप है, किंतु सामाजिक पूर्वाग्रहों को बदलने का कार्य नीति से अधिक समाज का है।

8. आलोचनात्मक मूल्यांकन

8.1 क्या NEP 2020 कोठारी से आगे जाती है?

एक दृष्टि से NEP 2020 कोठारी से आगे जाती है: वह बालपन की शिक्षा (ECCE) को मुख्य तंत्र में शामिल करती है, जो कोठारी नहीं कर पाए थे। वह 21वीं सदी के कौशल आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, सहयोग को शिक्षा के केंद्र में रखती है। और वह उच्च शिक्षा में लचीलापन लाकर छात्रों को अधिक विकल्प देती है। किंतु एक दूसरी दृष्टि से NEP 2020 कोठारी से पीछे भी हटती है: सामान्य विद्यालय प्रणाली का परित्याग, निजीकरण को प्रोत्साहन,

और वित्तीय प्रतिबद्धता की अनिश्चितता। द्रेज़ और सेन (2013) का यह तर्क आज भी प्रासंगिक है कि बिना सार्वजनिक निवेश के शिक्षा में समता असंभव है।

8.2 क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

NEP 2020 की सबसे बड़ी चुनौती क्रियान्वयन है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, अतः केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों ने NEP 2020 के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है विशेषकर भाषा-नीति और केंद्रीयकरण के मुद्दे पर। रैना (2002) की यह टिप्पणी कोठारी पर थी किंतु NEP 2020 पर भी लागू होती है: "नीति के प्रतिपादन और उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई भारतीय शिक्षा की अकिलीज़ हील (सबसे बड़ी कमजोरी) रही है।" बिना पर्याप्त शिक्षक, बुनियादी ढाँचे और वित्त के कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती।

9. निष्कर्ष

कोठारी आयोग (1966) और NEP 2020 के बीच का संबंध न तो पूर्ण निरंतरता का है और न पूर्ण विराम का यह एक जटिल "निरंतर परिवर्तन" का संबंध है। निरंतरता के धागे स्पष्ट हैं: शिक्षा को राष्ट्र-निर्माण का साधन मानना, मातृभाषा को महत्त्व देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल, सामाजिक समता का संकल्प, और शिक्षक की केंद्रीय भूमिका। ये मूल्य भारतीय शिक्षा-दर्शन की रीढ़ हैं। परिवर्तन के आयाम भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं: शैक्षणिक संरचना का पुनर्निर्माण, राज्य की बदलती भूमिका, भारतीय ज्ञान-परंपराओं का पुनर्आग्रह, डिजिटल तकनीक का प्रवेश, और उच्च शिक्षा में बहुलवाद। ये परिवर्तन वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति और राजनीतिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने जो बीज 1966 में बोए थे, NEP 2020 उन्हें एक नए मौसम में, नई मिट्टी में, नए जल से सींचने का प्रयास है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या भारतीय राज्य, समाज और शिक्षक मिलकर उस खाई को पाट सकते हैं जो नीति और व्यवहार के बीच दशकों से मुँह बाए खड़ी है। कोठारी के शब्दों में "कक्षा वह स्थान है जहाँ भारत का भाग्य निर्मित होता है।" आज भी उतने ही सत्य हैं जितने 1966 में थे। प्रश्न यही है: क्या हमारी कक्षाएँ उस गरिमा की अधिकारिणी बन पाई हैं?

संदर्भ सूची

प्राथमिक स्रोत:

कोठारी आयोग (1966). *शिक्षा और राष्ट्रीय विकास: शिक्षा आयोग* 1964-66 *की रिपोर्ट*। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार (1968). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, 1968। शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार (1986). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, 1986। मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

भारत सरकार (1992). *कार्यक्रम क्रियान्वयन* 1992। मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

भारत सरकार (2009). *बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम*, 2009। विधि और न्याय मंत्रालय।

कस्तूरीरंगन समिति (2019). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 2019 *का प्रारूप*। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत सरकार (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 2020। शिक्षा मंत्रालय।

द्वितीयक स्रोत:

एएसईआर (2018). *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण)* 2018। एएसईआर केंद्र, प्रथम।

एएसईआर (2021). *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट* 2021। एएसईआर केंद्र, प्रथम।

बेटेय, ए. (2010). *विश्वविद्यालय चौराहे पर*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

भट्टाचार्य, पी. (2021). "नई शिक्षा नीति 2020: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन।" *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 56(5), 23-30।

चट्टोपाध्याय, एस. (2021). "एनईपी 2020 और उच्च शिक्षा: संघवाद पर खतरा?" *जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी*, 36(3), 345-362।

देशपांडे, एस. (2020). "एनईपी 2020 को पढ़ना: पंक्तियों के बीच।" *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 55(34), 14-18।

द्रेज़े, जे., एवं सेन, ए. (2013). *अनिश्चित गौरव: भारत और उसके अंतर्विरोध*। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

कुमार, के. (2005). *शिक्षा का राजनीतिक एजेंडा: औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन* (द्वितीय संस्करण)। सेज पब्लिकेशंस।

नंबीसन, जी. बी. (2010). "शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामाजिक समावेशन।" *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 45(19), 18-26।

नंबीसन, जी. बी. (2020). "एनईपी 2020 और समानता: एक आलोचनात्मक दृष्टि।" *कॉन्टेम्परेरी एजुकेशन डायलॉग*, 17(2), 245-261।

रैना, वी. के. (2002). "कोठारी आयोग और उसके बाद की स्थिति।" *सोशल साइंटिस्ट*, 30(7/8), 47-64।

तिलक, जे. बी. जी. (2004). "उच्च शिक्षा में नीति और दृष्टिकोण का अभाव।" *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 39(21), 2159-2164।

तिलक, जे. बी. जी. (2018). "भारत में शिक्षा नीति: कोठारी से नई शिक्षा नीति 2016 तक।" *जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन*, 32(3), 231-259।

विश्व बैंक (2020). *विश्व विकास संकेतक: शिक्षा पर सरकारी व्यय*। वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।